ditions and environmental safeguards. All industries in the Himachal Pradesh have been directed to comply with prescribed standards within a time frame.

Incidents of Poaching by very influential people

4097. SHRI SOM PAL: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the fact that two detailed reports that have appeared in the Indian Express of 3rd February, 1993 and 22nd February, 1993 on incidents of poaching by very influential people;

(b) if so, what are the details of these incidents;

(c) what are the names of the persons, who have indulged in this highly illicit activity; and

(d) what action has been taken by Government against the persons involved therein?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI KAMAL NATH): (a) The report of 3rd February deals with illegal landing of helicopter in Corbett Tiger Reserve while the report of 22nd February deals with a review of Project Tiger areas. The linkage of any poaching by influential people in these reports are not yet established.

(b) The incidences of illegal landings were noted in April, 1991 and in October and December of 1992.

(c) and (d) A case against illegal landing of helicopter in Corbett Tiger Reserve by the India International Airways Private Limited has been instituted by the State Government. This Ministry has also taken up the matter with the State Government for early action in the case.

राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण का गठन

4098. **श्री अजीत जोगी :**
श्री छोटू भाई पटेल :

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण के गठन का प्रस्ताव काफी लंबे समय से लंबित है ;

(ख) यदि हां, तो यह कब से लंबित है तथा इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) उक्त न्यायाधिकरण का गठन कब तक किये जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमलनाथ) : (क) से (ग) किसी परिसंकटमय पदार्थ की उठाई-धराई के समय होने वाली किसी दुर्घटना से होने वाली क्षतियों के लिये बड़ा दायित्व निर्धारित करने और इस प्रकार की दुर्घटना से उत्पन्न मामलों के प्रभावी और शीघ्र निपटान के लिये राष्ट्रीय पर्यावरण अधिकरण की स्थापना करने के लिये 18 अगस्त, 1992 को लोक सभा में एक विधेयक पुरःस्थापित किया गया जिसका उद्देश्य व्यक्तियों, संपत्ति और पर्यावरण को हुई क्षति के लिये राहत और मुआवजे का व्यवस्था करना है ।

पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग के लिये जापान के साथ समझौता

4099. **श्री अजीत जोगी :**
श्री छोटू भाई पटेल :

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पर्यावरण के क्षेत्र में तथा अन्तर्राष्ट्रीय पर्यावरण संबंधी मामलों में सहयोग करने के लिये जापान से कोई समझौता किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या विश्वव्यापी पर्यावरणीय सुविधाओं का समर्थन करने, उनका उचित विकास तथा पुनर्गठन करने के लिये एक अन्तर्राष्ट्रीय आयोग स्थापित किये जाने के संबंध में सितम्बर, 1992 में नई दिल्ली में कोई वार्ता हुई थी ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमलनाथ) : (क) और (ख) : जापान ने विदेशी आर्थिक सहयोग निधि (ओ.ई.सी.एफ.) के तहत भारत को इंदिरा गांधी नहर के किनारे वनीकरण और चरागाह विकास से संबंधित परियोजनाओं के लिये 7869 मिलियन येन की और राजस्थान राज्य में अरावली की पहाड़ियों के वनीकरण की परियोजना के लिये 8095 मिलियन येन की सहायता प्रदान की है । इसके अलावा, यमुना कार्य योजना के लिये 17.77 बिलियन येन की सहायता देने का वचन दिया है ।

(ग) और (घ) सितम्बर, 1992 के दौरान जापान के राज्य मंत्री और पर्यावरण एजेंसी के महानिदेशक की भारत यात्रा के दौरान भारत और जापान के बीच पर्यावरण और वानिकी क्षेत्रों में द्विपक्षीय मामलों पर और जून, 1992 के दौरान रियो डि जैनेरो (ब्राजील) में आयोजित संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन में लिये निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिये संयुक्त राष्ट्र द्वारा गठित किये जाने वाले सतत् विकास संबंधी आयोग की संरचना और अधिदेश पर विचारों का आदान-प्रदान हुआ ।

Doubts on the East Coast Project's Environmental Impact

4100. SHRI M. A. BABY: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that serious doubts have been raised about the East Coast Road Project's environmental impact and economic viability;

(b) if so, what are the doubts raised; and

(c) what are Government's views on the issues involved?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI KAMAL NATH): (a) and (b) Certain organisations and individuals have expressed concern about the adverse environmental and socio-economic impacts of the proposed coastal road;

(c) The State Government has constituted a committee to study the proposal and submit a report on the actual situation in the field. An Environmental Impact Assessment Report prepared by the State Government has been submitted recently to the Ministry for its consideration.

Environmental problems in Sardar Sarovar Project

4101. SHRI MENTAY PADMANABHAM: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) what are the outstanding environmental problems in the Sardar Sarovar Project which have to be cleared;

(b) whether World Bank has given any deadline in this regard; and

(c) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI KAMAL NATH): (a) The Sardar Sarovar and Narmada Sagar Project were accorded environmental clearance in June, 1987 stipulating that environmental management plans will be evolved and implemented pari-passu with the construction work.